



# अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार




रजि.न.34300/80 | संख्या 287 | श्री विजय पुरम, मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए


# माननीय उप राज्यपाल ने प्रस्तावित आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल की तैयारियों की समीक्षा की

## पर्यटन विभाग को फेस्टिवल को भव्य, आकर्षक एवं व्यापक स्तर पर आयोजित करने का निर्देश

श्री विजय पुरम, 25 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल, डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय (आईपी एंड टी) द्वारा आयोजित किए जाने वाले वार्षिक आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल (द्वीप पर्यटन महोत्सव) के प्रस्तावित संस्करण पर प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण की विस्तृत समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान, माननीय उप राज्यपाल महोदय ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि फेस्टिवल का आयोजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भव्य, आकर्षक और व्यापक स्तर पर किया जाए, जिसका उद्देश्य अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और अपार पर्यटन क्षमता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित और प्रोत्साहित करना है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव, श्री ज्ञानेश भारती, आयुक्त सह सचिव (पर्यटन), माननीय उप राज्यपाल के सचिव, सचिव (सूचना प्रचार एवं पर्यटन), तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।









सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। सभी को ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही व निष्पक्षता के साथ कार्य करने, रिश्वत न लेने–न देने , नियमों का पालन करने तथा शिकयत निवारण व व्हिसल ब्लोअर तंत्र को सुदृढ़ करने का संकल्प दिलाया।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में निदेशक, केन्द्रीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)–केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआईएआरआई) श्री जय सुंदर एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमती शीला सिंह ने शिष्टाचार भेंट की।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में महर्षि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर अण्डमान में निवासरत वाल्मीकि समाज के सदस्यों के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों, विचारों एवं महान कृतित्व का स्मरण किया।

इस अवसर पर माननीय उप राज्यपाल महोदय ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन और उनकी अमर रचना रामायण हमें सत्य, धर्म, सदाचार एवं मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

इस अवसर पर श्री अजय कुमार वाल्मीकि, श्री किरण राज सिंह, श्री गोपी चंद एवं श्रीमती ममता सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के तहत अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, भा.प्र.से., ने आज सचिवालय क अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।

## समामेलित लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रारम्भ




श्री विजय पुरम, 26 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से वेतन निर्धारण, एमएसीपी और सूचना का अधिकार (आरटीआई) विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज से यहां के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय (टीजीसीई) की सेमिनार गैलरी में शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के समामेलित लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों

शेष पृष्ठ 4 पर

## अफ्रीकन स्वाइन फीवर की रोकथाम के लिए द्वीपों में जागरूकता, परामर्श एवं सैनिटाइज़ेशन अभियान तेज

श्री विजय पुरम, 26 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) के प्रसार को रोकने के लिए द्वीपसमूह में जागरूकता, परामर्श, जैव–सुरक्षा और सैनिटाइज़ेशन संबंधी गतिविधियों को तेज कर दिया है।




अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूअरों में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। यह मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता और मानव स्वास्थ्य के लिए इसका कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है और न ही इसका कोई विशिष्ट उपचार है। रोग पर नियंत्रण के लिए जैव–सुरक्षा के कड़े उपाय, पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण तथा बीमारी के लक्षणों की समय पर सूचना देना सबसे प्रभावी उपाय हैं। विभाग द्वारा सूअर पालकों

शेष पृष्ठ 4 पर

## अफ्रीकन स्वाइन फीवर की रोकथाम के लिए

पृष्ठ 1 का शेष

को फार्म की स्वच्छता, कीटाणुशोधन, बाहरी व्यक्तियों के अनावश्यक प्रवेश पर रोक, पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण, बीमारी की तत्काल सूचना देने तथा अन्य जैव–सुरक्षा उपायों के संबंध में परामर्श दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर जागरूकता बैठकें और शिविर आयोजित किए गए हैं।

लिटिल अण्डमान के आर. के. पुर में पंचायत भवन में जागरूकता बैठक आयोजित की गई, जिसमें सूअर पालकों, पशु सखियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों तथा विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और गैर–सरकारी संगठन कीया फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। हटबे स्थित रेंज कार्यालय में आयोजित जागरूकता शिविर के दौरान बीमारी की प्रकृति, इसके प्रसार के तरीकों और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। विशेष रूप से अण्डमान के जंगली सूअरों के संपर्क में आने या उनसे संबंधित गतिविधियों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर ज़ोर दिया गया। शिविर में हटबे रेंज तथा एएफईवीएस इकाई के कर्मचारियों सहित कुल 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

24 अक्टूबर को तरेसा द्वीप स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बंगाली में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा, डिगलीपुर, आर. के. ग्राम और सुभाषग्राम में घर–घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। आर. के. पुर में सैनिटाइज़ेशन गतिविधियां भी संचालित की गईं। 26 अक्टूबर को छोटा एनाका में प्रथम कैप्टन की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 25 लोगों ने भाग लिया। वहीं, ओंगी टेकरी स्थित सुनामी शेल्टर में 22 लोगों को जागरूक किया गया। इनमें अधिकांश उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, स्थानीय सूअर पालक तथा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्य शामिल थे। यहां जागरूकता गतिविधियों को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर यात्रियों और उनके सामान का सैनिटाइज़ेशन भी किया जा रहा है। कल एमवी नालंदा और एमवी सेंटिनल से आने वाले यात्रियों



तथा उनके सामान को सैनिटाइज किया गया। आज एमवी रानीचंगा से आने वाले यात्रियों और उनके सामान का सैनिटाइज़ेशन किया गया। चावरा जेटी पर रवाना होने वाले यात्रियों के हाथों और पैरों का सैनिटाइज़ेशन किया गया। आज एमवी कालीघाट से आने वाले यात्रियों का भी सैनिटाइज़ेशन किया गया। कैंपबेल बे में आज हेलीकॉप्टर से आने–जाने वाले यात्रियों और उनके सामान को भी उचित तरीके से सैनिटाइज किया गया। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पंचायत कार्यालयों में पोस्टर भी लगाए गए हैं। विभाग द्वारा पूरे द्वीपसमूह में जागरूकता, निगरानी और जैव–सुरक्षा संबंधी गतिविधियां लगातार जारी रखी जा रही हैं। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विभाग ने सूअर पालकों से अपील की है कि वे अपने सूअरों को सुरक्षित बाड़ों में रखें, साफ–सफाई बनाए रखें, अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करें तथा किसी भी असामान्य बीमारी या पशु की मृत्यु होने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। साथ ही, सूअरों, सूअर के मांस और उससे बने उत्पादों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता।

## समामेलित लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों

पृष्ठ 1 का शेष

के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संबंधित विषयों पर कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सचिव (प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण/पीजीसी) श्री सतनाम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कुशल प्रशासन के लिए कर्मचारियों की क्षमता का निरंतर विकास करने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) ने उप निदेशक सुश्री रिज़वाना बानो को प्रतिनियुक्त किया है, जो कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। वहीं, आईएसटीएम के उप निदेशक श्री एस. पी. एस. परिहार 28 अक्टूबर, 2026 से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे।



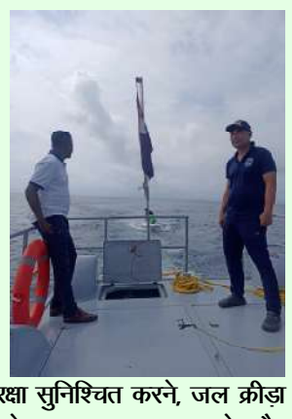



## समुद्री बल ने जेट स्की सवार को सुरक्षित बचाया, पलटी हुई जेट स्की को स्वराज द्वीप लाया

श्री विजय पुरम, 26 अक्टूबर।

नियमित समुद्री गश्त के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस समुद्री बल (पीएमएफ), स्वराज द्वीप इकाई ने 25 अक्टूबर, 2026 को लाइटहाउस क्षेत्र के निकट समुद्र में बहती हुई खराब जेट स्की को सुरक्षित रूप से खींचकर स्वराज द्वीप के फ्लोटिंग जेटी तक पहुंचाया। समुद्री गश्त के लिए एमवी जुल्फिकार अली को 25 अक्टूबर, 2026 को तैनात किया गया था। इस गश्ती दल में एसआई (एम) डी. एस. डेकाटे, एएसआई (एईडी) पेत्रुस कुजूर, पीसी/1883 सागर केरकेट्टा तथा एचसी/647 सॉ जैक्सन शामिल थे। दल ने स्वराज द्वीप के एलीफेंटा तट के आसपास समुद्री क्षेत्र में सुबह 9 बजे गश्त शुरू की और दोपहर 2.30 बजे वापस लौटा। गश्त के दौरान दल ने लाइटहाउस क्षेत्र के निकट एक जेट स्की को पलटी हुई अवस्था में समुद्र में बहते हुए देखा। जेट स्की का इंजन खराब हो गया था और उसका सवार भी उसके पास मौजूद था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस समुद्री बल के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए जेट स्की को सुरक्षित रूप से खींचा और स्वराज द्वीप स्थित फ्लोटिंग जेटी तक पहुंचाया। इस कार्रवाई से जेट स्की को सुरक्षित वापस लाने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक, पुलिस समुद्री बल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समय पर दी गई यह सहायता





पुलिस समुद्री बल की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, जल क्रीड़ा संचालकों एवं उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के तटीय समुद्री क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अण्डमान तथा निकोबार पुलिस का समुद्री बल समुद्र में सुरक्षित गतिविधियों को सुनिश्चित करने तथा समुद्री आपात स्थितियों के दौरान त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तटीय सुरक्षा को और मजबूत करने के उसके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

## खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते आइलैंड बीच गेम्स स्थगित

श्री विजय पुरम, 26 अक्टूबर।

पर्यटन निदेशालय द्वारा ज़िला प्रशासन (उत्तर व मध्य अण्डमान), खेल एवं युवा कार्य विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से 30 और 31 अक्टूबर, 2026 को दक्षिण अण्डमान के वंडूर तथा उत्तर अण्डमान के डिगलीपुर के रामनगर में आयोजित किए जाने वाले आइलैंड बीच गेम्स को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र, श्री विजय पुरम द्वारा जारी प्रतिकूल मौसम पूर्वानुमान के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यक्रम का सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एहतियातन यह कदम उठाया गया है। प्रतियोगिता की नई तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। हालांकि, पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वंडूर तट पर आयोजित होने वाली बीच वॉलीबॉल, रस्साकशी, आर्म रेसलिंग तथा 100 मीटर दौड़ आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए खेल एवं युवा कार्य विभाग के कोच श्री खालिद से मोबाइल नंबर 9434290640 पर संपर्क कर सकते हैं। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार वहीं, रामनगर तट, डिगलीपुर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए डिगलीपुर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) श्री बिजॉय हलदर से संपर्क कर सकते हैं।

## प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण संबंधी चुनौतियों पर कार्यशाला

श्री विजय पुरम, 26 अक्टूबर।

डॉ. एस. राधाकृष्णन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), गाराचरामा, दक्षिण अण्डमान द्वारा डी.ईआई.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण संबंधी चुनौतियों पर पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर, 2026 तक संस्थान के सभागार, गाराचरामा में किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य डी.ईआई.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न शिक्षण संबंधी चुनौतियों की पहचान करने, उन्हें समझने तथा उनका समाधान करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और व्यावहारिक रणनीतियों से सुसज्जित करना है। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण, बहुस्तरीय एवं बहुभाषी कक्षाओं का प्रभावी प्रबंधन, सीखने में मौजूद कमियों को दूर करना, विद्यार्थियों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, समावेशी एवं बाल–केंद्रित शिक्षण पद्धतियों को लागू करना,





उपयुक्त शिक्षण–अधिगम सामग्री का चयन तथा प्रभावी कक्षा मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों की सहभागिता, बुनियादी शिक्षा तथा समग्र शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए नवाचारी, चिंतनशील और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षण पद्धतियां विकसित करने के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

## फोटोग्राफी एवं कैमरा संचालन पर प्रशिक्षण का शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 26 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग ने नोएडा स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी (आईआईपी) के सहयोग से आज फोटोग्राफी एवं कैमरा संचालन पर आठ दिवसीय गहन प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पहल 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' (रैम्प) योजना के तहत संचालित की जा रही है। यह विश्व बैंक के सहयोग से समर्थित एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) को सशक्त बनाना है। इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में कैमरा संचालन, पेशेवर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पोस्ट–प्रोडक्शन, ड्रोन इमेजिंग तथा अंडरवाटर फोटोग्राफी और एस्ट्रोफोटोग्राफी जैसे विशेष क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नोएडा स्थित आईआईपी के अनुभवी प्रशिक्षक श्री आसिफ खान और सुश्री गरिमा चौधरी 60 प्रतिभागियों के समूह को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन प्रतिभागियों का चयन द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, लॉन्ग आइलैंड, लिटिल अण्डमान और कैंपबेल बे शामिल हैं, से किया गया है। प्रशिक्षण के पहले दिन कैमरा तकनीकों की बुनियादी जानकारी पर केंद्रित परिचयात्मक सत्र आयोजित किया गया। इसमें एक्सपोज़र ट्रायंगल के प्रमुख घटकों–अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ–के मूल सिद्धांतों, कैमरा संचालन की सही तकनीक तथा प्रकाश मापने की व्यावहारिक विधियों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को विभिन्न परिवेशीय प्रकाश परिस्थितियों में कैमरे की कार्यप्रणाली समझने पर विशेष ज़ोर देते हुए शुरुआत से ही व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया। इस क्षमता–विकास



पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं की तकनीकी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करना है, ताकि वे अपने स्वयं के व्यावसायिक उद्यम स्थापित कर सकें और एमएसएमई के तहत औपचारिक पंजीकरण के माध्यम से संगठित क्षेत्र से जुड़ सकें। यह पहल रैम्प योजना के उद्देश्यों के अनुरूप है।

स्थानीय प्रतिभाओं को पेशेवर उद्योग मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करके इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीपसमूह में आने वाले पर्यटकों को प्रशिक्षित फोटोग्राफरों एवं वीडियोग्राफरों की सेवाएं उपलब्ध कराना भी है, ताकि वे यहां के प्रसिद्ध प्राकृतिक दृश्यों और समुद्री स्थलों पर अपनी यादगार यात्राओं को खूबसूरत तस्वीरों एवं वीडियो के रूप में संजो सकें। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण के बाद पर्यटन विभाग प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इसके अगले चरण आयोजित करेगा। इसके तहत स्वराज द्वीप में 3 नवंबर तथा शहीद द्वीप में 12 नवंबर, 2026 से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

## राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर लॉन्ग आइलैंड में जागरूकता कार्यक्रम संचालित

श्री विजय पुरम, 26 अक्टूबर।

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2026 के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) द्वारा 23 और 24 अक्टूबर को मध्य अण्डमान के लॉन्ग आइलैंड में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आम जनता के बीच प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण, उचित अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की स्मृति में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लॉन्ग आइलैंड में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कर्मचारियों ने पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों एवं अन्य उपस्थित लोगों को पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए 'स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी: सतत जीवन की ओर एक कदम' विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कुमार पी. जसवंत ने प्रथम, कुमार आयुष मिंज ने द्वितीय तथा कुमारी कृतिका जिया केरकेट्टा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य श्रीमती दीपा नायर ने विजेताओं को क्रमशः 2,500 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये की नकद




पुरस्कार राशि प्रदान की। इसके अतिरिक्त, लॉन्ग आइलैंड में आयोजित अभियान के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों एवं आम जनता को प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रधान श्री बी. कामराजू ने स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं को रेखांकित किया। उन्होंने द्वीप की संवेदनशील प्राकृतिक पर्यावरण व्यवस्था को सुरक्षित रखने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कचरे के उचित निपटान के महत्व पर ज़ोर दिया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जन–जागरूकता पहल के तहत पंचायत प्रतिनिधियों एवं आम जनता के बीच 'स्वच्छता ही सेवा' तथा 'स्वच्छ राष्ट्र बनाना है, हर घर से प्लास्टिक को हटाना है' संदेश अंकित कपड़े के थैलों का वितरण भी किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना था।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

# अहमदाबाद को मिली सीनियर वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2029 की मेजबानी

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

गुजरात का अहमदाबाद शहर 2029 में सीनियर भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस खेल की अंतरराष्ट्रीय संस्था (आईडब्ल्यूएफ) ने रविवार को चीन के निंग्बो में हुई अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। इस तरह भारत में पहली बार सीनियर भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। आईडब्ल्यूएफ ने अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में 2029 और 2030 की सीनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए मेजबान शहरों का चयन किया। वर्ष 2030 की प्रतियोगिता रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की जाएगी।

आईडब्ल्यूएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 की विश्व युवा चैंपियनशिप की मेजबानी कोसोवो के प्रिश्टिना और विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी वेनेजुएला की राजधानी काराकास को सौंपने का भी फैसला किया। आईडब्ल्यूएफ के महासचिव जोस क्विनोनेस ने कार्यकारी बोर्ड के मतदान के बाद कहा,श्हमें जो भी मेजबानी के प्रस्ताव मिले, वे सभी उत्कृष्ट थे। हमें पूरा विश्वास है कि आपके संबंधित देशों में होने वाली चैंपियनशिप बेहद सफल रहेंगी।

उन्होंने कहा, यह भी उल्लेखनीय है कि इन चार में से तीन देश कोसोवो, वेनेजुएला और भारत पहली बार आईडब्ल्यूएफ



की किसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। यह दर्शाता है कि हमारा खेल दुनियाभर में विस्तार कर रहा है और कई देशों के लिए हमारी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करना बेहद आकर्षक है।

आईडब्ल्यूएफ ने कहा कि उसने आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के कैलेंडर को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक साथ चार विश्व चैंपियनशिप के मेजबान देशों को चुनने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अहमदाबाद 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की भी मेजबानी करेगा। इसके अलावा भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी दावेदारी कर रहा है। (भाषा)

# नशा मुक्ति पर बड़ा कदम, 10 हजार स्वास्थ्यकर्मी होंगे प्रशिक्षित

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (हि.स.)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन–1 में नशा मुक्ति सेवाओं से जुड़े चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत मार्च 2029 तक देशभर में 10,000 स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकारों की पहचान, आकलन, उपचार और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की दक्षता बढ़ाना है। इसके अंतर्गत डॉक्टरों, मेडिकल अधिकारियों, नर्सों, काउंसलरों, मनोवैज्ञानिकों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस अवसर पर श्री जेपी नड्डा ने कहा कि वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक कल्याण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।

यह कार्यक्रम जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जारी नारकोटिक कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026–2029 के अनुरूप संचालित किया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में 2,000, वर्ष 2027–28 में 3,000 और वर्ष 2028–29 में 5,000 सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम छह केंद्रीय संस्थानों के माध्यम से संचालित होगा। इनमें एम्स नई दिल्ली, गाजियाबाद, निम्हंस बेंगलुरु, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली और एम्स भुवनेश्वर शामिल हैं। इस पहल का समन्वय एम्स करेगा।

कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन लाइव सत्र, स्व–गति ऑनलाइन पाठ्यक्रम और पांच दिवसीय प्रत्यक्ष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों के लिए 12 सप्ताह तक साप्ताहिक ऑनलाइन सत्र आयोजित होंगे। पाठ्यक्रम में शराब, गांजा, ओपिओइड, नींद की गोलियों और इनहेलेंट्स के सेवन से संबंधित विकारों के उपचार के साथ महिलाओं और किशोरों की विशेष जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

इस दौरान श्री जेपी नड्डा ने नशे के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर तैयार मैन्युल के दूसरे संस्करण का भी विमोचन किया। वर्ष 2005 में पहली बार प्रकाशित इस पुस्तिका को नशे की लत से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी, उपचार पद्धतियों और चिकित्सा सेवाओं में हुए बदलावों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा संबंधित संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी शामिल हुए।

# सेना को हमेशा आगे रहने के लिए नई क्षमताओं के साथ बेहतर तरीके खोजने होंगे

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (हि.स.)।

पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि सेना को हमेशा आगे रहने के लिए न केवल नई क्षमताएं विकसित करनी होंगी, बल्कि अपने मौजूदा मिलिट्री प्लेटफॉर्म को ज्यादा असरदार, जानलेवा और ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए बेहतर तरीके भी खोजने होंगे। उन्होंने कहा कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सटीक हथियार और दूसरी नई टेक्नोलॉजी आज के समय में युद्ध लड़ने के तरीके को बदल रही हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह सोमवार को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 'मेकेनाइजेशन टेक्नोलॉजी संगोष्ठी 2.0' (एमटीएस 2.0) के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन पश्चिमी कमान ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) के सहयोग से किया था।

उन्होंने चंडीगढ़ के चंडीमंदिर मिलिट्री स्टेशन में 14–15 दिसंबर को 'भविष्य के युद्ध के लिए वर्तमान प्लेटफॉर्म का रूपांतरण' थीम पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी। इसमें भारतीय सेना, रक्षा उद्योग और शिक्षा जगत के हितधारक एकत्रित होंगे, ताकि मशीनीकृत बलों की प्रौद्योगिकीय प्रगति और उनकी क्षमता संवर्धन पर चर्चा की जाएगी।



उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भारतीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे मौजूदा कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को भविष्य के युद्ध के मैदान में एक अहम बढ़त मिल सके। जो बात इस पहल को अलग बनाती है, वह है हमारा बॉटम–अप अप्रोच।

हमारे सैनिकों को जमीन पर असल में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और टेक्नोलॉजी उनसे निपटने में कैसे मदद कर सकती है? इन ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर हमने खास समस्याओं की पहचान की है और प्रॉब्लम डेफिनिशन स्टेटमेंट बनाए हैं, जिन्हें हम इंडियन इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडेमिया के साथ शेयर कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए प्रैक्टिकल, सस्ते और इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं।

# टीबी और फेफड़ों के कैंसर की जल्द पहचान में मददगार हो सकता है एआई

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भारत में तपेदिक (टीबी) और फेफड़ों के कैंसर से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, एआई की मदद से इन बीमारियों की शुरुआती पहचान, तेजी से जांच और मरीजों की स्क्रीनिंग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

इस विषय पर 22 से 25 अक्टूबर तक जयपुर में आयोजित नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस, इंडिया और इंडियन चेस्ट सोसाइटी के 28वें संयुक्त वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में विस्तार से चर्चा हुई। इस सम्मेलन में भारत और विदेशों से 2,000 से अधिक फेफड़ों एवं श्वसन रोग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन में एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि एआई श्वसन संबंधी बीमारियों की पहचान और उनके उपचार के तरीके में बदलाव ला सकता है। उन्होंने बताया कि एआई आधारित उपकरण छाती के एक्स–रे और सीटी स्कैन में संदिग्ध असामान्यताओं की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। इससे डॉक्टरों को आगे की जांच और उपचार के संबंध में तेजी से और बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।

डॉ. गुलेरिया ने कहा कि श्वसन संबंधी बीमारियों की शुरुआती पहचान के तरीके में बदलाव लाने की एआई में क्षमता है। छाती के एक्स–रे और सीटी स्कैन में संदिग्ध संकेतों की पहचान करके यह तकनीक डॉक्टरों को समय पर जांच कराने और उचित उपचार की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकती है।

सम्मेलन में विशेषज्ञों ने बताया कि एआई आधारित सॉटवेयर छाती के एक्स–रे का विश्लेषण कर सकता है और टीबी से जुड़े संकेतों की पहचान कर सकता है। इससे स्वास्थ्यकर्मियों को उन मरीजों को प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है, जिन्हें आगे की जांच की जरूरत है।



विशेषज्ञों के अनुसार, यह तकनीक उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर वहां जहां विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

सम्मेलन में फेफड़ों के कैंसर की पहचान में एआई की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि उन्नत एआई एल्गोरिदम डॉक्टरों को सीटी स्कैन की जांच करने, फेफड़ों में संदिग्ध गांठों की पहचान करने और उन असामान्यताओं को चिह्नित करने में मदद कर सकते हैं, जिनकी आगे जांच जरूरी हो सकती है।

# उपग्रह टैग लगाए गए दो अमूर बाज़, अपापांग और अलांग, एशिया और अफ्रीका के तेईस देशों की यात्रा पूरी कर मणिपुर लौटे

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (हि.स.)।

प्रवासी पक्षियों की लंबी और रोमांचक यात्रा का एक और अध्याय पूरा हो गया है। अमूर फाल्कन 'अपापांग' और 'अलंग' करीब 11 दिन पहले उत्तर–पूर्वी चीन के अपने प्रजनन स्थलों से उड़ान भरने के बाद मणिपुर पहुंच गए हैं। इन दोनों पक्षियों ने एशिया और अफ्रीका के रास्ते अपनी यात्रा के दौरान 23 देशों को पार किया। इसके साथ ही नवंबर, 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के वैज्ञानिकों द्वारा टैग किए जाने के बाद उनकी लगभग एक साल की ट्रैकिंग और मणिपुर तक वापसी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'एक्स' पर दोनों पक्षियों की तस्वीरें साझा कर बताया कि दोनों अमूर फाल्कन अब मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाकों में चुनिंदा स्थानों पर दो से तीन सप्ताह तक रुक सकते हैं। यहां स्थानीय लोग हर साल इन प्रवासी पक्षियों की वापसी का इंतजार करते हैं और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रवास के दौरान अमूर फाल्कन अपने ठहराव वाले क्षेत्रों में निकलने वाले दीमकों को खाकर शरीर में वसा का भंडार बढ़ाएंगे। यह ऊर्जा उनकी अगली लंबी उड़ान के लिए बेहद जरूरी है। मणिपुर से आगे बढ़ने के बाद इन पक्षियों को सोमालिया तक लगभग 6,000 किलोमीटर की उड़ान भरनी होगी। इस यात्रा में वे करीब छह दिनों तक बिना रुके उड़ान भर सकते हैं। इस मार्ग में लगभग 3,000 किलोमीटर तक अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरना भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इन पक्षियों के प्रवासी मार्गों, व्यवहार और लंबी दूरी की उड़ान को समझने के लिए पिछले साल




यानी नवम्बर, २०२५ में 'मणिपुर अमूर फाल्कन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट' शुरू किया। इस परियोजना के जरिए वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद मिल रही है कि ये पक्षी किन रास्तों से गुजरते हैं, कहां ठहरते हैं और समुद्र के ऊपर लंबी उड़ान के दौरान किस तरह अपनी यात्रा पूरी करते हैं।

परियोजना के दूसरे चरण में नवंबर, 2025 में मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के चिउलुआन रोस्टिंग स्थल से तीन अमूर फाल्कन को सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाकर छोड़ा गया था। इनमें अपापांग नाम का नर पक्षी और आहू तथा अलांग नाम की दो मादा पक्षी शामिल थीं। इन पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखकर वैज्ञानिकों ने उनकी अंतरमहाद्वीपीय यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं। अब अपापांग और अलांग की मणिपुर वापसी से उनके प्रवास चक्र के अध्ययन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अमूर फाल्कन अपनी लंबी दूरी की प्रवास यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। छोटे आकार के ये पक्षी मौसम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। चीन से एशिया और अफ्रीका तक की उनकी यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण और पक्षियों की निगरानी के महत्व को रेखांकित करती है।

# आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ा चक्रवात 'अर्नब', 28 अक्टूबर को तट से टकराने की आशंका, अलर्ट जारी

हैदराबाद, 26 अक्टूबर (हि.स.)।

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव तेज होकर 'चक्रवात अर्नब' में बदल चुका है। इसके आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने के साथ ही राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवात 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने, जबकि झोंकों की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।

चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने, संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते सतर्क करने और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में करीब छह लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तटीय इलाकों में स्कूल–कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 अक्टूबर की आधी



रात तक चक्रवात अर्नब गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। इसके बाद 27 अक्टूबर को यह बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

चक्रवात के 28 अक्टूबर को उत्तर–पश्चिम की ओर बढ़ने और बापटला तथा विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार करने की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय, यनम और रायलसीमा में अलग–अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ तूफान आने की संभावन है। 29 अक्टूबर को भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है।

# सरकार ने मनस्तु स्पेस के साथ किया समझौता

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर

भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने और अंतरिक्ष तक टिकाऊ पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (टीडीबी) ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 116 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहायता अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) फंड के तहत प्रदान की जाएगी।

कुल 277.63 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए 5 मिली–न्यूटन (एमएन) से 300 न्यूटन (एन) तक की थ्रस्ट क्षमता वाले एकीकृत और विस्तार योग्य (स्केलेबल) ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का विकास करना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (टीआरएल)–6 से बढ़ाकर टीआरएल–9 तक पहुंचाना है, जिससे इसके विकास, परीक्षण और व्यावसायिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सके। परियोजना को वित्तीय सहायता ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट (ओसीडी) के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

# इतिहास के पन्नों में 27 अक्टूबरः संघर्ष से राष्ट्रपति भवन तक का सफर, के.आर. नारायणन की प्रेरक कहानी

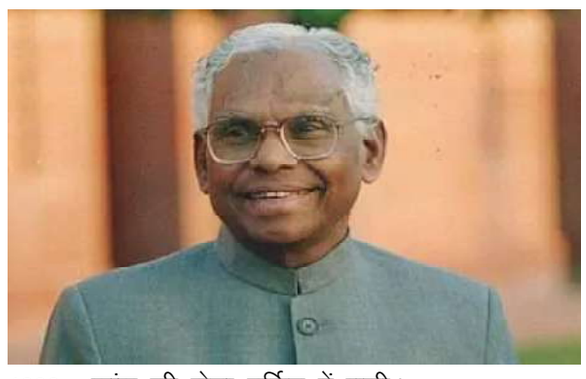
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (हि.स.)।

देश के पहले दलित राष्ट्रपति केआर नारायणन की जयंती 27 अक्टूबर को मनाई जाती है। 27 अक्टूबर 1920 को तत्कालीन त्रावणकोर रियासत के उझावूर गांव में जन्मे कोचेरिल रमण नारायणन ने कठिन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा हासिल कर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल है।

नारायणन का बचपन अभावों में बीता, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता और विदेश सेवा के क्षेत्र में काम किया। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में उन्होंने विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कूटनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।

राजनयिक सेवा के बाद नारायणन ने राजनीति में कदम रखा। वह लोकसभा के सदस्य बने और केंद्र सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्ष 1992 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। इसके पांच वर्ष बाद, 1997 में वह भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 2002 तक इस पद पर कार्य किया और देश के पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया।

राष्ट्रपति के रूप में नारायणन ने संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक समानता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने राष्ट्रपति पद को केवल औपचारिक संवैधानिक भूमिका तक सीमित न रखते हुए लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी भूमिका निभाई।



महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1676– पोलैंड और तुर्की ने वारसा की संधि पर हस्ताक्षर किए।
1795– अमेरिका और स्पेन ने सैन लोरेंजो की संधि पर हस्ताक्षर किए।
1806– फ्रांस की सेना बर्लिन में घुसी।
1810– अमेरिका ने स्पेन के पूर्व उपनिवेश पश्चिमी फ्लोरिडा को अपने अधिकार में लिया।
1905– नार्वे स्वीडन से अपना गठजोड़ समाप्त करके स्वतंत्र हो गया।
1910– रूस और चीन के साथ कई वर्षों के युद्ध के बाद जापान को इन दोनों देशों पर विजय मिली।
1920– लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा स्थानांतरित किया गया।
1924– उज़्बेक एसएसआर सोवियत संघ में मिला।
1946– फ्रांस में जनमत संग्रह के बाद इस देश के चौथे राष्ट्रपतिकाल के संविधान को जनता की स्वीकृति मिली।
1947– राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू–कश्मीर के विलय को स्वीकार कर लिया।
1958– पाकिस्तान के राष्ट्रपति स्केदर मिर्जा को अपदस्थ कर जनरल अय्यूब खां पाकिस्तान के शासक बने।
1959– पश्चिमी मेक्सिको में चक्रवाती तूफान से कम से कम 2000 लोग मरे।
1968– मेक्सिको सिटी में 19वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ।
1982 – चीन ने अपनी जनसंख्या एक अरब से अधिक होने की घोषणा की।
2003 – चीन में भूकम्प से 50,000 से अधिक लोग प्रभावित।

# रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा बलों के लिए लगभग 2 लाख 12 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न रक्षा उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें थल सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल, स्वचालित ट्रैक्ड गन सिस्टम, हल्के बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, निगरानी ड्रोन और लंबी दूरी की ड्रोन प्रणाली सहित कई उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है।



हाई मोबिलिटी व्हीकल से मुश्किल इलाकों में सेना की आवाजाही, परिचालन क्षमता और लॉजिस्टिक मदद बेहतर होगी। वहीं स्वचालित ट्रैक्ड गन सिस्टम से सेना की मशीनीकृत टुकड़ियों को बेहतर गतिशीलता और मारक क्षमता मिलेगी। हल्के बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल सेना और वायु सेना, टोही और निगरानी, युद्ध अभियानों, सैनिकों की खोज और बचाव तथा आपदा राहत कार्यों के लिए होगा। निगरानी और ड्रोन प्रणालियों से सेना की निगरानी और लक्ष्य साधने की क्षमता बढ़ेगी।

नौसेना के लिए एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम और अन्य प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे दुश्मन की आधुनिक एंटी–शिप मिसाइलों के खिलाफ मिसाइल रक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी होगी। वहीं वायु सेना के लिए हेलीकॉप्टर, वायु रक्षा प्रणाली, हथियार और मोबाइल एक्स–बैंड डॉप्लर मौसम रडार प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। विशेष उपयोग वाले हेलीकॉप्टरों से वायु सेना की हवाई परिवहन संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। एक्स–बैंड डॉप्लर मौसम रडार से अग्रिम क्षेत्रों में मौसम की सटीक जानकारी और स्थानीय स्तर पर निगरानी की जा सकेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन खरीद प्रस्तावों में से लगभग 82 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी।

# सरकार ने 100% इथेनॉल वाले ई100 फ्यूल को दी मंजूरी, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में नहीं होगा इस्तेमाल

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन अधिसूचित कर दिया। इसके साथ ही, 100 प्रतिशत इथेनॉल वाले E100 फ्यूल से चलने वाली फ्लेक्स–फ्यूल गाड़ियों का रास्ता साफ हो गया है। फ्लेक्स–फ्यूल गाड़ियां E85 (85 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) और 100 प्रतिशत इथेनॉल वाले E100 ईंधन पर चलने के लिए भी सक्षम बनाए जाते हैं।




मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि 20 प्रतिशत से ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में किया जा सकेगा, जिन्हें ज्यादा इथेनॉल से चलाने के लिए डिजाइन और प्रमाणित किया गया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 20 प्रतिशत इथेनॉल वाले E20 पेट्रोल या सामान्य पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में E85 या E100 फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

नियमों में किए गए संशोधन के तहत वाहन वर्गीकरण की कुछ सीमाओं, ईंधन विनिर्देशों और उत्सर्जन संबंधी परीक्षणों में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी संदर्भों में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा, इन बदलावों से प्रभावित हल्के पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए वजन की सीमा 3000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3500 किलोग्राम कर दी गई है।

सरकार कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। देश में काफी पहले E20 पेट्रोल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। मारुति सुजुकी इंडिया ने इस साल जून में देश का पहली फ्लेक्स–फ्यूल पैसेंजर कार वैगनआर लॉन्च किया था, जो E20 से लेकर E100 फ्यूल से भी चल सकती है।

मारुति के अलावा, टोयोटा, टाटा मोटर्स और हुंडई समेत अन्य ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां भी भारतीय बाजार के लिए फ्लेक्स–फ्यूल गाड़ियां डेवलप कर रही हैं। मंत्रालय ने इससे पहले व्हीकल एमिशन नियमों में भी संशोधन का प्रस्ताव दिया था, ताकि ज्यादा इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन और वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जा सके। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य E85 और E100 के साथ E100 बायोडीजल और हाइड्रोजन–सीएनजी मिश्रित फ्यूल के इस्तेमाल का प्रावधान करना था।

# आसियान रक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक में भाग लेंगे रक्षा मंत्री

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 28 और 29 अक्टूबर को फिलीपींस के सेबू में होने वाली आसियान रक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक–प्लस (एडीएमएम–प्लस) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रक्षा मंत्री बैठक से अलग भागीदार देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इस दौरान श्री सिंह इन देशों के साथ रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, संगठन में रक्षा संबंधी विचार–विमर्श और सहयोग का सर्वोच्च मंच है। एडीएमएम–प्लस, आसियान के सदस्य देशों और उसके 8 संवाद साझेदारों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग मजबूत करने का एक मंच है। इन साझेदारों में अमरीका, चीन, रूस, जापान और न्यूजीलैंड शामिल हैं।

भारतीय खाद्य निगम, डॉलीगंज, श्री विजय पुरम

**निविदा सूचना**

FCI, डॉलीगंज, श्री विजय पुरम में हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए GeM पोर्टल पर 'टू पैकेट सिस्टम' (Two Packet System) के तहत ऑनलाइन बोलियां (bids) आमंत्रित की जाती हैं।

बिड नंबर : GEM/2026/B/8179867
अनुमानित मूल्य : रु. 25,00,000/– (केवल पच्चीस लाख रुपये)
अनुबंध की अवधि : 06 (छह) महीने
समापन तिथि एवं समय : 29/10/2026 को अपराहन 17.00 बजे
खुलने की तिथि एवं समय : 30/10/2026 को अपराहन 17.00 बजे

सम्पूर्ण जानकारी, कार्य का विवरण और सबमिशन संबंधी आवश्यकताओं के लिए ऊपर दिए गए बिड नंबर का उपयोग करके GeM पोर्टल पर जाएं।

मंडल प्रबंधक,
एफसीआई, डीओ, श्री विजय पुरम

# पढ़ाई से नौकरी तक का रास्ता आसान बनाने पर जोर, सीबीएसई का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों की पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने के विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि स्कूल से निकलने के बाद उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और नौकरी की दुनिया में भी आसानी से आगे बढ़ सकें। यानी हुनर को पढ़ाई जैसी अहमियत मिलेगी।



यह आयोजन सोमवार 26 अक्टूबर व 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे के जरिए छात्रों के कौशल को शिक्षा व्यवस्था के अलग–अलग स्तरों पर मान्यता देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद है कि छात्रों की सीखने की प्रक्रिया केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित न रहे, बल्कि उनके व्यावहारिक ज्ञान और हुनर को भी महत्व मिले। इसके साथ ही स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा को सामान्य पढ़ाई का हिस्सा बनाने के तरीकों पर चर्चा हो रही है। इससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही कामकाज की दुनिया की जरूरतों को समझने और भविष्य के लिए जरूरी क्षमताएं विकसित करने का अवसर मिल सकेगा।

'स्कूल से कामकाजी दुनिया तक की राह आसान बनाना' विषय पर आयोजित इस चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में स्कूलों के प्रमुख, शिक्षक, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विद्यालय संगठनों के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हो रही है कि बदलती जरूरतों के हिसाब से छात्रों को कैसे तैयार किया जाए।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव टी के अनिल कुमार और सीबीएसई के अध्यक्ष डॉ. मंदीप भंडारी भी सम्मेलन में मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए टी के अनिल कुमार ने चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात कही। इनमें तकनीक, डिजिटल सुरक्षा और कौशल; डिजाइन, रचनात्मकता और नए प्रयोग; शिक्षा के अलग–अलग स्तरों पर कौशल को मान्यता देना तथा सभी छात्रों के लिए समान अवसरों के साथ करियर मार्गदर्शन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की पढ़ाई, उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। इससे छात्रों को अपने भविष्य के बारे में सोच–समझकर फैसले लेने में मदद मिलेगी। वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। समाज में योगदान दे सकेंगे और सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन में शिक्षा के नए तरीकों, मूल्यांकन की बदलती व्यवस्था और पढ़ाई में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी विचार–विमर्श किया जा रहा है। (इनपुट–एजेंसी)

# ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय वीजा आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक नियमों का किया विस्तार

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में वीजा आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी देने की आवश्यकताओं का विस्तार किया है। इसके तहत आवेदकों से उंगलियों के निशान और चेहरे की तस्वीर मांगी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य वीजा प्रणाली को सुरक्षित, प्रभावी और भरोसेमंद बनाए रखना है।

सोमवार से भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बायोमेट्रिक जानकारी देनी पड़ सकती है। यह नियम 26 अक्टूबर या उसके बाद जमा किए गए आवेदनों पर लागू होगा। पहले से जारी वीजा या इस तारीख से पहले जमा किए गए आवेदनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों का विभाग आवेदकों को सूचित करेगा कि उन्हें बायोमेट्रिक जानकारी देने की जरूरत है या नहीं। जरूरत होने पर उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। बयान के अनुसार, आवेदकों की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर उन्हें भारत में वीएफएस ग्लोबल द्वारा संचालित 16 ऑस्ट्रेलियाई बायोमेट्रिक संग्रह केंद्रों में से किसी एक पर जाने के लिए कहा जा सकता है। कुछ आवेदक ऑस्ट्रेलियाई इमी ऐप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी करने के पात्र हो सकते हैं। आमतौर पर इसकी सूचना आवेदक या उनके अधिकृत एजेंट को ईमेल के जरिए दी जाएगी।

ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के मुताबिक, बायोमेट्रिक कार्यक्रम का विस्तार आवेदकों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करेगा। भारत से बड़ी संख्या में लोग ऑस्ट्रेलिया में घूमने, पढ़ाई करने, काम करने और अन्य संबंध विकसित करने के लिए जाते हैं। ऐसे में सरकार वीजा प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखना चाहती है।

उच्चायोग ने कहा कि बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने से वीजा प्रक्रिया में लगने वाले समय पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पहले से करीब 60 देशों में वीजा आवेदकों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करता है। भारत को इस कार्यक्रम में शामिल करने से उसकी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। पात्र आवेदकों को ऑस्ट्रेलियाई इमी ऐप के जरिए डिजिटल विकल्प भी मिलेगा।

# सरकार ने रिलीफ पहल को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाया, खाड़ी क्षेत्र में निर्यात को मिलेगी सुरक्षा

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

वाणिज्य विभाग ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत समयबद्ध उपाय, रिलीफ (निर्यात सुविधा के लिए गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स कदम) के घटक II के तहत समयसीमा 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दी है। रिलीफ घटक II निर्यात के लिए ईसीजीसी कवर को बढ़ावा देने के लिए 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज देता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।

मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में निरंतर भू–राजनीतिक व्यवधानों और खाड़ी एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में समुद्री लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रभाव को देखते हुए 30 सितंबर, 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026–27 के माध्यम से विस्तार को अधिसूचित किया गया था। इस पहल के घटक II का उद्देश्य निर्यातकों को विशिष्ट क्षेत्रों में होने वाले निर्यात हेतु एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) कवर लेने के लिए बढ़ावा देना है, जिसमें 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज दिया जाएगा। यह लाभ 16 मार्च, 2026 को या उसके बाद ली गई एकल पॉलिसी और सम्पूर्ण टर्नओवर पॉलिसी के लिए उपलब्ध है। इस घटक के तहत योग्य निर्यातकों द्वारा दिया जाने वाला प्रीमियम निर्धारित अवधि के दौरान बाधा–पूर्व स्तर से अधिक बढ़ने पर सुरक्षित रहता है। कवर की गई कार्गो श्रेणियों में फुल कंटेनर लोड (एफसीएल), लेस दैन कंटेनर लोड (एलसीएल) और रेफ्रिजरेटेड (रीफर) कंटेनर शामिल हैं। लेकिन इनमें ऊर्जा निर्यात शामिल नहीं हैं।



रिलीफ पहल के तहत कवरेज चाहने वाले निर्यातकों को ईसीजीसी कस्टमर पोर्टल www.ecgcltd.in के ज़रिए दावा और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। इस पहल के तहत यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने, निर्यातक पंजीकरण पूरा करने और दावा जमा करने के बारे में दिशा–निर्देश ईसीजीसी के आधिकारिक यू–ट्यूब चैनल, @ecgcltd7016 पर समर्पित वीडियो ट्यूटोरियल के ज़रिए मिल जाएंगे।

19 मार्च, 2026 को लॉन्च किया गया रिलीफ एक लक्षित कदम है जो उन भारतीय निर्यातकों की मदद के लिए है जो माल ढुलाई की लागत में अत्यधिक बढ़ोतरी, उच्च बीमा प्रीमियम और खाड़ी तथा विस्तृत पश्चिमी एशियाई समुद्री गलियारे में रुकावटों की वजह से युद्ध से उत्पन्न निर्यात जोखिमों का सामना कर रहे हैं।

# चक्रवात अर्नब का नाम किसने रखा? जानें इसका मतलब और नामकरण का पूरा नियम

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।

बंगाल की खाड़ी के पूर्व–मध्य और दक्षिण–पूर्व में बना गहरा दबाव अब 'चक्रवात अर्नब' में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 26 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। यह तूफान आंध्र प्रदेश तट के करीब से गुजर सकता है और एक बेहद खतरनाक चक्रवात का रूप ले सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, अर्नब का मतलब क्या है और यह नाम कौन तय करता है?



अर्नब नाम बांग्लादेश ने दिया है। यह नाम उत्तरी हिंद महासागर (जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल हैं) में आने वाले तूफानों की आधिकारिक लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट को अप्रैल 2020 में अपनाया गया था। इसमें 13 देशों के दिए गए कुल 169 नाम हैं। हर देश ने 13 नाम दिए हैं। इन देशों में बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं।

जैसे ही कोई तूफान चक्रवात की कैटेगरी में आता है, तो पहले से तय लिस्ट के हिसाब से उसे नाम दे दिया जाता है। लिस्ट में किसी देश का नाम होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तूफान उसी देश में आएगा या वहीं टकराएगा।

बंगाली भाषा में अर्नब का मतलब समुद्र या महासागर होता है। IMD की आधिकारिक लिस्ट में इस नाम को मंजूरी दी गई है और इसका उच्चारण "ओर्नब" बताया गया है। हालांकि, इसका कोई औपचारिक विवरण नहीं दिया गया है। यह नाम एक साझा क्षेत्रीय सिस्टम का हिस्सा है, जहां देश तूफान आने से पहले ही अपने सुझाए गए नाम लिस्ट में दे देते हैं।

नई दिल्ली में मौजूद प्डक का क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र इन तूफानों का नाम तय करता है। जब उत्तरी हिंद महासागर (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर) में उठने वाला तूफान एक तय स्पीड पार कर लेता है, तब उसे नाम दिया जाता है।

यह केंद्र उन नामों का इस्तेमाल करता है जो 13 देशों ने मिलकर तय किए हैं। नाम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तूफान कहां टकराएगा, बल्कि यह लिस्ट के क्रम के हिसाब से चुना जाता है। इसलिए, भले ही नाम बांग्लादेश ने दिया हो, लेकिन तूफान भारत के तट पर टकरा सकता है। नाम सिर्फ तूफान की पहचान के लिए होता है। मौसम विज्ञानी इसके रास्ते और टकराने की जगह का अलग से अनुमान लगाते हैं।

नाम रखने से मौसम विभागों, रेस्क्यू टीमों, मीडिया और आम लोगों को किसी खास तूफान के बारे में बात करने और उसे पहचानने में आसानी होती है। इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, खासकर तब जब एक ही समय में कई तूफान एक्टिव हों। इसके अलावा, चेतावनी जारी करने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में भी मदद मिलती है।

उत्तरी हिंद महासागर में तूफानों का नाम रखने का सिलसिला सितंबर 2004 में शुरू हुआ था। तब 8 देशों ने मिलकर नाम दिए थे। बाद में इस सिस्टम को और बड़ा किया गया। अप्रैल 2020 में जारी नई लिस्ट में 5 और देशों को शामिल किया गया, जिससे इनकी संख्या 13 हो गई। हर देश ने 13 नाम दिए, इसलिए मौजूदा लिस्ट में कुल 169 नाम हैं। हर नए तूफान के लिए नया नाम सोचने के बजाय, लिस्ट में मौजूद अगले नाम का इस्तेमाल किया जाता है।

बिल्कुल नहीं। तूफान के नाम से यह पता नहीं चलता कि वह कहां जाएगा, कितना ताकतवर होगा या कहां टकराएगा। यह सिर्फ एक पहचान है। जैसे, अर्नब नाम बांग्लादेश ने दिया है, लेकिन इसके आंध्र प्रदेश तट की ओर जाने का अनुमान है। तूफान का रास्ता, उसकी ताकत और टकराने की जगह वहां के मौसम और समुद्र की स्थिति पर निर्भर करती है, न कि उस देश पर जिसने नाम दिया है।

# भारतीय ओलंपिक संघ ने डकार युवा ओलंपिक खेलों के लिए घोषित किया भारतीय दल

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (हि.स.)।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने सोमवार को सेनेगल में होने वाले डकार 2026 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय दल की घोषणा कर दी है। भारत की ओर से 11 खेलों में 17 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। युवा खिलाड़ियों के लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने, दुनिया भर के खिलाड़ियों से सीखने और अपने खेल करियर में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 207 प्रतिनिधिमंडलों के लगभग 2,700 युवा खिलाड़ियों के 25 खेलों में हिस्सा लेने की उम्मीद है। युवा ओलंपिक खेलों में आयोजन के समय 17 वर्ष तक की आयु वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रतियोगिता के साथ खिलाड़ियों को सीखने और विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर भी मिलता है। भारतीय ओलंपिक संघ के लिए यह आयोजन दुनिया भर की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के साथ संपर्क बढ़ाने और प्रतिभाओं की पहचान, खिलाड़ियों के विकास तथा युवा खेलों से शीर्ष स्तर तक पहुंचने के रास्तों पर विचारों का आदान–प्रदान करने का अवसर भी होगा। इन चर्चाओं से भारत की खेल संबंधी योजनाओं को दिशा देने में मदद मिल सकती है। भारत की नजरें अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों पर भी हैं। इसके साथ ही अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए अधिक मजबूत और टिकाऊ अवसर तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। डकार खेलों के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा के नामीबिया और मॉरीशस सहित कई अफ्रीकी देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के साथ खेल सहयोग और आदान–प्रदान संबंधी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है।